

पर्यावरण

साझीदारी के जरिए संरक्षण

प

पर्यावरण के क्षेत्र में अमेरिका-भारत के बीच हो रहा सहयोग दोनों देशों के संबंधों में हो रहे बदलाव की असाधारण मिसाल है। पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निबटने में अमेरिकी विदेश विभाग (डॉस) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) की बदलती भूमिका और भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एन्वार्यर्मेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए), डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (डीओई), यू.एस. फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस (यूएसएफडब्लूएस) तथा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फियर एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) जैसी नई अमेरिकी संस्थाओं के आविर्भाव से पर्यावरण से जुड़े मसलों तथा पर्यावरण संबंधी साझा चिंताओं वाले मुद्दों से निबटने में अमेरिका-भारत की साझीदारी की गहराई और विस्तार का पता चलता है। पिछले दशक में भारत में अब तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। अमेरिका-भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों से साझीदारी करके—भारत की जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर पड़ने वाला असर दूर करने में मदद कर रहा है। अमेरिकी सरकार भारत में टिकाऊ विकास की खातिर साझीदारी के कई तरीके विकसित कर रही है। इस अध्याय में उन्हीं अहम तरीकों में से कुछेक को रेखांकित किया गया है।

डॉस और यूएसएड की गतिविधियां न केवल दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के इतिहास को जाहिर करती हैं बल्कि वे पर्यावरण के मामलों में अमेरिका-भारत के बीच लगातार बढ़ रहे सहयोग की भी मिसाल हैं। यूएसएड को भारत के समक्ष मौजूद विकास संबंधी चुनौतियों पर काम करने का लंबा अनुभव है, लिहाजा बदलते राजनैतिक और आर्थिक माहौल के प्रति उसकी प्रतिक्रिया हमेशा तेज और विशिष्ट होती है। यूएसएड के पर्यावरण विभाग ने मुख्यतः ऊर्जा और पर्यावरण के रिश्तों पर ध्यान दिया है। समय के साथ-साथ बुनियादी संरचना विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण और उसके व्यापारीकरण तथा ग्रीनहाउस गैस

खत्म करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। यूएसएड द्वारा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने से भारत में एक और जहाँ अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नियंत्रित करने में भी लाभ हुआ।

भारत में ग्रीनहाउस गैस नियंत्रित करने से विश्व पर्यावरण के साथ ही भारत में मानव स्वास्थ्य को भी कई लाभ होंगे। इसके अलावा, अमेरिकी गतिविधियों से विश्व के पर्यावरण में हो रहे बदलाव की समस्याओं से निबटने में मदद मिलेगी, जिसका भारत के बानिकी व जैवविविधता से संबंधित मामलों में परोक्ष ही सही पर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। जलवायु में गर्मी के बढ़ते रहने से जलमग्नता, अधिक बाढ़ या खारे पानी के प्रदूषण के कारण भारत के समुद्रतटीय इलाकों में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। कृषि पैदावार घट सकती है जिससे जमीन पर अधिकाधिक खेती की जाने लगेगी। पारिस्थितिकी में इतना परिवर्तन हो सकता है कि पहले से ही विलुप्त हो रही ढेर सारी प्रजातियों पर और खतरा मंडराने लगेगा।

इन खतरों से निबटने में सहायता और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नेतृत्व में “अमेरिका-भारत जलवायु परिवर्तन साझीदारी” के तहत भारत में कई तरह की नई गतिविधियां शुरू की गई हैं। यूएसएड ने कई परियोजनाओं का समन्वय करने और उन्हें धन मुहैया कराने की अपनी भूमिका बखूबी निभाकर तथा अमेरिकी सरकार की दूसरी एजेंसियों की व्यावहारिक मदद करके पर्यावरण की समस्याओं

अमेरिका ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संचय परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराया है



से निबटने में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और अधिक टिकाऊ साझीदारी विकसित करने में मदद दी है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और हाइड्रोजन ऊर्जा के नए क्षेत्र में काम करते हुए अमेरिकी ऊर्जा विभाग के साथ सुदृढ़ साझीदारी स्थापित की गई है। इससे भारत को ऐसे मुकाम पर पहुंचने में मदद मिलेगी जहां अर्थिक विकास, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण पर एक साथ काम किया जाता है। एक और मजबूत साझीदारी यू.एस. एन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) के साथ की गई है। यू.एस.-एशिया एन्वायर्नमेंटल पार्टनरशिप (यू.एस.-ईपीए) की बदौलत ईपीए भारत में शहरी वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन और विषेश पदार्थों के निबटान व उनके प्रबंधन जैसे अहम पर्यावरण संबंधी मामलों पर यूएसईपीए और भारतीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के बीच लगातार बढ़ रहे सहयोग में रणनीतिक तौर पर हिस्सेदारी करता है। इस पुस्तिका के “ऊर्जा” वाले अध्याय में भारत में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से संबंधित विभिन्न अमेरिकी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

मार्च 2000 में राष्ट्रपति बिल किंलटन की यात्रा ने पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों में निरंतर जारी सहयोग को रेखांकित किया। उस अहम दौरे के बाद भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री टी.आर. बालू और ईपीए के प्रशासक क्रिस्टीन टॉड व्हिटमैन ने 16 जनवरी, 2002 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा यू.एस. ईपीए के बीच पांच वर्ष के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से भारतीय शहरों में कई महत्वपूर्ण पहल की गई। मिसाल के तौर पर भारत के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों में से एक पुणे में वायु प्रदूषण प्रबंधन का कार्यक्रम, जिसमें शहर की वायु की गुणवत्ता की प्रबंधन रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए विज्ञान आधारित मॉडलों को प्रयोग करने का प्रयास किया गया।

जनसाधारण के स्तर पर अभियानों की विविधता इस मामले में अहम है। जैसे कोलकाता में जल आपूर्ति व्यवस्था का आधुनिकीकरण जैसी बड़ी परियोजनाएं या फिर साइकिल रिक्शा की पुनर्रचना (रीडिजाइनिंग) जैसी छोटी परियोजनाएं। यू.एस.-ईपीए समर्थित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कृष्णा सपूर्ण एक हाइड्रोजन-स्कूटर के विकास पर काम करने के लिए अपनी छुट्टी के दौरान भारत आई थीं। उन्होंने कहा, “लोग नहीं बातें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वे अनिच्छा नहीं दिखाते। उनकी जरूरतें बहुत कम हैं। उनकी मानसिकता बदलाव स्वीकार करने की है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें, किसी भी दूसरी अच्छी पर्यावरण संबंधी साझीदारी की तरह, विज्ञान और मानवता एक-दूसरे पर कुछ हद तक छा जाते हैं।”

प्रदूषण के खिलाफ पुणे ने उठाया पहला कदम

पुणे हाराष्ट्र में पुणे के सबसे अधिक भीड़ भेरे हिस्से एक ऐसे प्रयोग के लिए आदर्श इलाके हैं जो भारत के सैकड़ों शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। ईपीए के साथ भारत सरकार के सहमति पत्र के रूप में यू.एस.-ईपीए और पुणे नगरपालिका (पीएमसी) ने भारत में पहला इंटरनेशनल वेहिक्यूलर इमिशन मॉडल (आईवीईएम) अध्ययन किया है। इसके आंकड़ों से पुणे की वायु गुणवत्ता का मॉडल तैयार किया जाएगा और उसके नतीजों के आधार पर दूसरे शहरों के पर्यावरण में सुधार के प्रयासों में मदद दी जाएगी। इस अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय साझीदारों को शामिल किया गया जिन्होंने पुणे की सड़कों पर गाड़ियों के काफिले का मॉडल तैयार करने के लिए एक साथ काम किया। रिवरसाइड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ग्लोबल स्टेनेबल रिसर्च के साथ आईवीईएम डिजाइन किया। ईपीए का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर मॉडल, आईवीईएम वाहनों के प्रदूषण के स्तर का आकलन करता है। पुणे की सड़कों पर यातायात के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कई स्वयंसेवियों, पीएमसी के कर्मचारियों, पुणे विश्वविद्यालय, ईधन व वाहन कंपनियों, और इसमें दिलचस्पी रखने वाले नागरिकों को शामिल किया। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए यातायात के प्रवाह के बारे में आंकड़े जुटाए गए। इस अध्ययन से



फोटोग्राफर हुसेन/इंडिया टुडे

अमेरिका की एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज इंक. और भारत की बजाज ऑटो हाइड्रोजन चालित स्कूटर पर कार्यरत हैं।

भारत का पहला सदाबहार बिजनेस सेंटर

दराबाद स्थित ग्रीन बिजनेस सेंटर (जीबीसी) पर्यावरण के क्षेत्र में भारत-अमेरिका संबंधों का साकार रूप है। हाई-टेक सिटी में स्थित जीबीसी को प्रतिष्ठित लीड (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एन्वायर्नमेंटल डिजाइन) की प्लैटिनम रेटिंग मिली है। पर्यावरण के अनुकूल स्थापत्य को प्रोत्साहन देने वाली विश्व की प्रमुख संस्था में से एक यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की यह सबसे बड़ी रेटिंग है। परिकल्पना के लिहाज से जीबीसी अद्वितीय भवन है। इसमें ऊर्जा क्षमता, जल प्रबंधन, रिसाइकिलिंग प्रौद्योगिकियों और हरित भवन के विशेषज्ञों की मदद ली गई है। राख की ईंटों से बना जीबीसी हरित डिजाइन के मामले में न केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है, बल्कि यह अपने स्थानीय प्राकृतिक दृश्य के भी अनुरूप है।



जीबीसी में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), आंध्र प्रदेश सरकार, यू.एस.एड और हाउस ऑफ गोदरेज की हिस्सेदारी है। इन सबने पर्यावरण के अनुकूल इस इमारत के निर्माण में 22.65 करोड़ रु. (50 लाख डॉलर) लगाए हैं। सीआईआई ने वर्ष 2005 तक भारत के विभिन्न शहरों में 10 और जीबीसी बनाने का लक्ष्य रखा है।

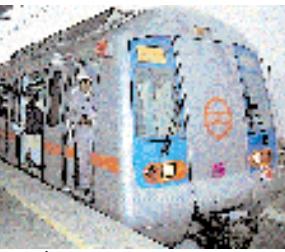
अनोखी विशेषताएं

भारत में जीबीसी जैसी डिमार्टों गिनती की ही है।

- जीबीसी वाहनी निर्माण व भीतर की गतिविधि के मामले में आदर्श हारित भवन है।
- जीबीसी के पास पर्यावरण संरक्षण के विशेषज्ञ हैं जो उद्योग से मशविरा करते हैं।
- जीबीसी 50-60 फीसदी अधिक ऊर्जा सक्षम हैं। उसमें 25 फीसदी बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से किया जाता है।
- यह राख की ईंटों से बना है। राख पास के बिजलीघरों से अवशिष्ट के रूप में निकलती है।
- घास की हरित छत से यह भीतर से ठंडा रहता है।



एनवाईसीटी के अजय सिंह दिल्ली मेट्रो की साइट पर। वे इसे भावी ट्रांजिट सिस्टम का आदर्श बनाने में मदद कर रहे हैं।



शरद सक्षेणा

**दुनिया भर में
केवल न्यूयॉर्क
सिटी ट्रांजिट
और दिल्ली मेट्रो
ही आईएसओ
14001 प्रमाणपत्र
हासिल करने में
सफल हुए हैं। यह
दिल्ली मेट्रो की
बड़ी उपलब्धि है।**

न्यूयॉर्क सबवे से लेकर दिल्ली मेट्रो तक

जब यूएस-ईपी ने न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट (एनवाईसीटी) के चीफ एन्वायर्नमेंटल एंड स्टेनेबिलिटी ऑफिसर के रूप में पदोन्नत अजय सिंह से दिल्ली मेट्रो के लिए काम करने के लिए संपर्क किया तो यह उनके लिए माकूल विकल्प था। उन्होंने 1985 में एनवाईसीटी में सहायक इंजीनियर के बॉर्डर काम शुरू किया। वे उस टीम के सदस्य हैं जिसने उसे आईएसओ 14001 दिलाने में मदद की। एनवाईसीटी इसे हासिल करने वाली पहली यातायात व्यवस्था थी। 2002 में एनवाईसीटी और दिल्ली मेट्रो ने ऐसा खाका तैयार किया जिससे दिल्ली मेट्रो को आईएसओ 14001 मिला। इसकी प्राप्ति अमेरिका-भारत साझीदारी और दिल्ली मेट्रो की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता की गवाही देती है। दिल्ली मेट्रो एनवाईसीटी की खूबियां अपनाने जा रही हैं। एनवाईसीटी की खूबियां हैं: कम ऊर्जा व कागज की खपत वाले दफतर, ऐसे स्टेशन जिनमें सौर फलक लगे हों और निर्माण के 85 फीसदी कचरे की रीसाइकिलिंग। अजय सिंह का मानना है कि इस बारे में मानक तय करने से दिल्ली मेट्रो को बढ़त मिल गई है जिससे यह ऐसे आदर्श नेटवर्क के रूप में स्थापित हो गया जिसका दुनिया भर के मास ट्रांजिट सिस्टम को अनुसरण करना चाहिए।

हाइड्रोजन—ईधन जो जीवन बदल सकता है

ज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन दुनिया के काम करने और काम पर जाने के ढंग को बदल सकती है। भारत को अपनी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अहम कामयाबी मिलने वाली है। ठोस अवस्था वाली हाइड्रोजन के संचय की प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ अमेरिका की एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज (ईसीडी) इंक. और भारत की बजाज ऑटो के बीच वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की पहचान की खातिर भारत-अमेरिका में सहयोग चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में उपभोक्ताओं की पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोत की जरूरत को पूरा करना है। इसी के तहत हाइड्रोजन से चलने वाला गैर-प्रदूषणकारी तिपहिया तैयार किया जा रहा है। ईसीडी ने व्यापार के लिए हाइड्रोजन से चलने वाले तिपहिया की प्रमुख वाहन और भारत की प्रमुख बाजार के रूप में पहचान की है। ईसीडी की हाइड्रोजन संचय प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ भारतीय वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले तिपहिए से भारत पर्यावरण संबंधी अपनी सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं में एक से बच्ची निबट सकता है। पारंपरिक ऊर्जा से चलने वाले दोपहिए और तिपहिए वाहन तथा बिजली के जनरेटर प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। हाइड्रोजन चालित तिपहिए धातु की हाइड्राइड संचय इकाइयों में रखी हाइड्रोजन से चलते हैं। ऐसे वाहन और जनरेटर भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी साबित हो सकते हैं।

सीमाओं से परे वन्य जीवन

यह हम जानते हैं: कि पृथ्वी मानव जाति की नहीं है। मानव जाति पृथ्वी की है।” दुनिया भर के संरक्षणवादी इस धारणा को मानते हैं कि दुनिया की समृद्ध जैव विविधता ऐसा खजाना नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष की जागीर हो। दुनिया की लुप्तप्राय प्रजातियों पर किसी तरह का हमला खुद प्रकृति पर हमला है। लिहाजा, उसकी रक्षा भी दुनिया भर की जिम्मेदारी बन जाती है।

वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत-अमेरिका की साझेदारी इसी का परिवर्तित रूप है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों में सहयोग के मुख्य प्रेरक, यू.एस. फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस (यूएसएफडब्लूएस) के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम ‘वाइल्डलाइफ विदआउट बॉर्डस’ बिल्कुल माकूल है। भारत, जहां पौधों की 21,000, स्तनपायियों की 500 और चिड़ियों की 1,500 प्रजातियां हैं, को जैव विविधता के केंद्रों में छठा स्थान हासिल है। लेकिन आधुनिकीकरण की मांग ने देश की प्रजातियों की अद्भुत विविधता के सामने निरंतर चुनौती खड़ी कर दी है।

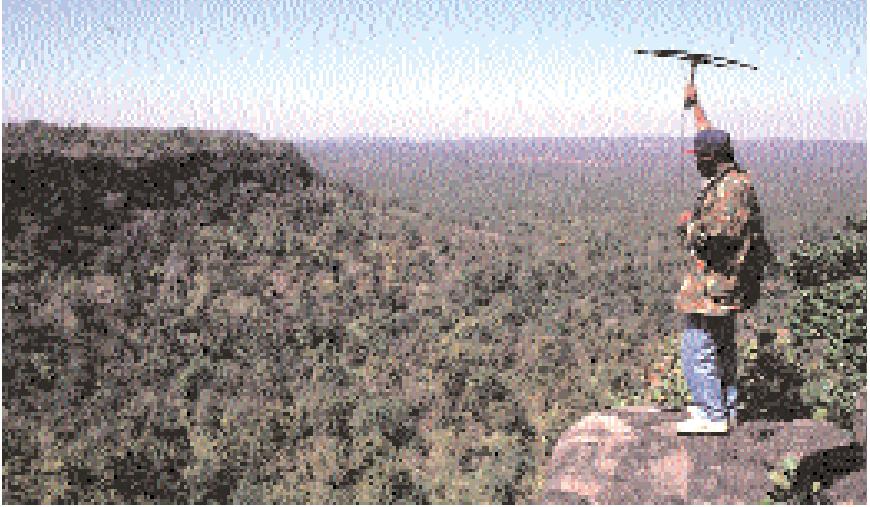
1973 के एंडेंर्ड स्पीशीज एक्ट के चलते यूएसएफडब्लूएस को दुनिया भर में



पश्चिमी घाट का दक्षिणी
हिस्सा (नीचे) जहां अब बहुत
कम वन क्षेत्र बचा है

सभी फोटो: एस.यू. श्रवण कुमार





पन्ना बाघ अभयारण्य में भालू का पता लगाता एक संरक्षणवादी

महत्वपूर्ण कदम तस्करी पर नजर

देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में भारत की पहली वन्यजीव फॉरेंसिक प्रयोगशाला पशु-तस्करी के खिलाफ लंबी लड़ाई में बड़ा कदम है। यह यूएसएफडब्लू-



एस की मदद से बनी है। डब्लूआइआइयूएसएफडब्लू-एस कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट के बोडल अफसर बी.सी. चौधरी कहते हैं, “पशु तस्करों के खिलाफ मामला इतना ठोस हो ताकि उन्हें दोषी सिद्ध किया जा सके।”

लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करने का अधिकार मिल गया। यूएसएफडब्लूएस ने अमेरिकी दूतावास के विज्ञान विभाग के जरिए भारत सरकार व निजी संगठनों से हाथ मिलाकर वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन, प्राकृतिक वास के बचाव तथा संरक्षण पर ध्यान दिया। कोष के लिए उसने अमेरिकी स्वामित्व वाले भारतीय रूपयों, जिन्हें डॉलर में नहीं बदला जा सकता था और भारत में ही खर्च किया जाना था, का प्रयोग किया। इस राशि को दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं में लगाना था। भारत सरकार ने कुछ संस्थाओं को सहयोगी के रूप में चुना जिसमें मुख्यतः निजी पैसे से चलने वाली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) व सरकारी भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्लूआईआई) थे।

1883 में गठित पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाले भारत के अहम केंद्र, बीएनएचएस के साथ यूएसएफडब्लूएस की साझीदारी में पक्षियों की आवाजाही व उनके प्राकृतिक वास की निगरानी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी का अध्ययन तथा गोडावण और साइबेरियाई क्रेन के प्राकृतिक वास के अध्ययन की परियोजनाएं शामिल थीं। यूएसएफडब्लूएस ने डब्लूआईआई के साथ क्षमता निर्माण और आधुनिक अनुसंधान की तकनीक के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया।

डब्लूआईआई में भारत की पहली (और इकलौती) फॉरेंसिक वन्यजीव प्रयोगशाला के साथ ही वन्यजीव स्वास्थ्य विशेषज्ञों का नेटवर्क, वाइल्डलाइफ हेल्प कोअॉपरेटिव, इसी साझीदारी का नतीजा था। जारी परियोजनाओं में पन्ना टाइगर रिज़र्व में स्लॉथ भालू के पारिस्थितिकी तंत्र व दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के खिंडंग का जैव विविधता पर असर जाने आदि अनुसंधान शामिल हैं। आम तौर पर माना जाता है



अमेरिका की व्यायाता से भारत में हाथियों की संख्या बढ़ाए रखने में मदद मिल सकती है

कई सत्कार्य

यूएसएफडब्लूएस और उपकी भारतीय साझीदारी फिलहाल सक्रिय है

- बीएनएचएस के साथ शोला और एल्पाइन घास के मैदानों की पारिस्थितिकी।
- खच्छ जल वाले दलदलों की जैव विविधता का संरक्षण।
- भारतीय वन्यजीव व्यास के साथ हाथियों के प्रवास के रास्तों की पहचान।
- डब्लूआईआई के साथ बाघ संरक्षणवादियों का प्रशिक्षण।
- बीएनएचएस के साथ हिमालय के निचले इलाकों में गिर्बों के घोंसलों की निगरानी।
- डब्लूआईआई के साथ पूर्वोत्तर भारत में हूलॉक गिर्बन का सर्वेक्षण व उनके संरक्षण के उपाय।

कि खासकर किसी इलाके की किसी लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण से उस प्रजाति के पूरे प्राकृतिक वास की रक्षा स्वतः होने लगती है। मसलन, काज़ीरंगा में गेंडे के प्राकृतिक वास के संरक्षण से दलदली हिरण जैसे जानवरों की भी देखभाल हो जाती है। मछली और वन्यजीव विज्ञानी फ्रेड बैगले का कहना है कि काज़ीरंगा परियोजना “आदर्श कार्यक्रम” है।

धन की कमी के कारण वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत-अमेरिका संबंध आज दोराहे पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी मदद से बाघ, गेंडे और हाथी जैसी प्रजातियों को फायदा होगा, लेकिन यूएसएफडब्लूएस और भारतीय संरक्षणवादियों के सामने मुख्य चुनावी बुनियादी स्तर पर विकास के प्रयासों को जारी रखने के तरीके ढंगने की होगी। 4.52 करोड़ रु. (10 लाख डॉलर) के कोष से गठित इंडो-यूएस साइंस फोरम एक रास्ता मुहैया करा सकता है। लेकिन नई दिशा का सबसे तेज संकेत बाइ-नेशनल साइंस फाउंडेशन बनाने के प्रस्ताव से मिलता है। इसके लिए शुरू में भारत और अमेरिका को 226.25 करोड़ रु. (5 करोड़ डॉलर) का अनुदान देना है। बैगले भारत-अमेरिका संरक्षण साझेदारी में कई साझीदारों की राय का हवाला देते हुए कहते हैं, “भारत में संरक्षण को लोकर अमेरिका में काफी चिंता है। हम अपनी गतिविधियां बंद नहीं होने देना चाहते। हम उन्हें टिकाऊ बनाना चाहते हैं।”

अमेरिकी दूतावास के विज्ञान विभाग ने अपनी गतिविधियों से भारत में पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग ने भारतीय और अमेरिकी तकनीकी एजेंसियों को मिलाकर ऐसा माहौल तैयार किया है जिसमें पर्यावरण और संरक्षण में सहयोग फल-फूल सके।